



दलौदा पुलिस ने वाहन चोरी का किया खुलासा, तीन बाइक बरामद



एक वाहन चोर गिरफ्तार, सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी तक पहुंची पुलिस

मंदसौर। जिले की दलौदा थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे और उसकी

निशानदेही पर चोरी की तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2.40 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार, 26 सितंबर को ग्राम रोला, थाना रिंगनोद निवासी मुकेश पाटीदार ने दलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने विनायक स्कूल के सामने अपनी हीरो

स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक MP43DS4051 खड़ी की थी। करीब आधे घंटे बाद लौटने पर मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप डोंगी ने टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास और आने-जाने वाले मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने निम्नोद निवासी राजू पिता मोहनलाल मीणा (30) को गिरफ्तार किया। पुछताछ में पुलिस को दलौदा थाना क्षेत्र में अन्य स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी किए जाने की जानकारी मिली। आरोपी की निशानदेही पर धुंधड़का और दलौदा से चोरी की गई दो अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। बरामद वाहनों में हीरो स्प्लेंडर प्लस क्रमांक MP43DS4051, हीरो सुपर स्प्लेंडर क्रमांक MP14ZL5922 और हीरो सुपर स्प्लेंडर क्रमांक MP14MU7124 शामिल हैं। पुलिस ने तीनों वाहनों की कुल कीमत करीब 2.40 लाख रुपए बताई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप डोंगी, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र त्रिवेदी, प्रधान आरक्षक दोपेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक यादवेन्द्र सिंह, आरक्षक सुनील यादव और आरक्षक युवराज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कहानी बदलाव की, चिया सीड की खेती से बदली तस्वीर, गोपाल ने बढ़ाया मुनाफा



मंदसौर। जिले के सीतामऊ विकासखंड के ग्राम नाटा राम निवासी किसान गोपाल माली ने परंपरागत खेती से हटकर औषधीय फसल चिया सीड की खेती को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आत्मा परियोजना के मार्गदर्शन और निशुल्क बीज की मदद से उन्होंने चिया सीड की वैज्ञानिक तरीके से खेती की और इसे गेहूं की तुलना में अधिक लाभकारी पाया। नवाचार से पहले गोपाल माली गेहूं, सरसों सहित अन्य पारंपरिक फसलें लेते थे। उनके अनुसार इन फसलों में लागत अधिक होने के बावजूद उत्पादन और बाजार भाव अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाता था। इसके बाद उन्होंने आत्मा परियोजना के माध्यम से चिया सीड की खेती के बारे में जानकारी ली। परियोजना के वैज्ञानिकों ने खेती से संबंधित आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दिया और निशुल्क बीज भी उपलब्ध कराया। गोपाल माली के अनुसार गेहूं की खेती में प्रति बीघा करीब 17,300 रुपए लागत आती थी, जबकि चिया सीड की खेती में यह लागत घटकर करीब 10,100 रुपए प्रति बीघा रह गई। चिया सीड से प्रति बीघा करीब ढाई क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। बाजार मूल्य के आधार पर उन्हें प्रति बीघा करीब 37,500 रुपए की आमदनी हुई, जबकि गेहूं से प्रति बीघा करीब 31,500 रुपए की आमदनी होती थी। इस तरह कम लागत में चिया सीड की खेती से बेहतर आमदनी मिलने पर गोपाल माली ने इसे खेती में नया प्रयोग बताया। उन्होंने आत्मा परियोजना के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताते हुए प्रधानमंत्री रेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त किया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मासोद में 204 हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण, 30 यूनिट रक्तदान

बैतूल। 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में 28 सितम्बर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मासोद में स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ श्री भास्कराव मगरदे द्वारा किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप धुर्वे द्वारा दी गई जानकारी अनुसार स्वास्थ्य शिविर में 204 हितग्राहियों का पंजीयन कर स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार दिया गया। आयोजित रक्तदान शिविर में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप धुर्वे, बीपीएम श्री सुनील खात्रीकर के साथ-साथ स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग के 10 स्टाफ द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर में कुल 30 यूनिट रक्तदान हुआ। मासोद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा शिविर को सफल बनाने में सहयोग दिया गया। शिविर में मेडिकल ऑफिसर, बीईई, सीएचओ एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए परिवेश पोर्टल पर आवेदन का विभागों को दिया गया प्रशिक्षण

बैतूल। वन भूमि का नियमानुसार गैर वानिकी उपयोग किए जाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में परिवेश पोर्टल पर अनुमोदन के लिए आवेदन करने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, वन मंडल अधिकारी श्री नवीन गर्ग, वन मंडल अधिकारी श्री अरिहंत कोचर, सीईओ जिला पंचायत श्री गणेश जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों को परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी एवं प्रक्रियागत कठिनाइयों का समाधान करना है, ताकि भविष्य में वन भूमि से संबंधित प्रकरणों में आवेदन की प्रक्रिया सुगम हो और प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहें। प्रशिक्षण के दौरान वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग में लेने, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों, सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया तथा वन अधिकार प्रमाण-पत्र से संबंधित जानकारी दी गई।

दलोदा ग्राम पंचायत में EOW की कार्रवाई, सरपंच और पति रिश्तत लेते रंगे हाथ पकड़े

मन्दसौर। जिले के दलोदा ग्राम पंचायत में अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के एवज में रिश्तत मांगने के आरोप में सोमवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) उज्जैन की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने ग्राम पंचायत की सरपंच दुर्गा कैथवास और उनके पति व सरपंच प्रतिनिधि अनिल कैथवास को कथित रूप से 3500 रुपए की रिश्तत लेते रंगे हाथ पकड़ा। कार्रवाई के बाद ग्राम पंचायत में दस्तावेजों और अन्य प्रकरणों की जांच भी की गई। जानकारी के अनुसार दलोदा निवासी विक्रम सिंह पिता तख्ता सिंह ने EOW उज्जैन को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि लोन के दस्तावेजों के लिए आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के बदले सरपंच पति द्वारा 5 हजार रुपए की रिश्तत मांगी गई। शिकायतकर्ता



द्वारा आपत्ति जताने पर कथित रूप से 4 हजार रुपए में प्रमाण पत्र जारी करने की बात तय हुई। शिकायत मिलने के बाद EOW टीम ने सत्यापन और कार्रवाई की योजना बनाई। शिकायतकर्ता को टीम की ओर से

3500 रुपए दिए गए और इन्हें रिश्तत के रूप में देने के लिए कहा गया। सोमवार को शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत पहुंचा और सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि को उनके कक्ष में रुपए दिए। इसी दौरान EOW की टीम ने

कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद दोपहर करीब 1 बजे से ग्राम पंचायत में दस्तावेजों और अन्य मामलों से संबंधित जांच शुरू की गई, जो खबर लिखे जाने तक करीब पांच घंटे से जारी थी। EOW अपराध शाखा के अन्वेषण अधिकारी डीएसपी रामनिवास यादव ने बताया कि विक्रम सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। शिकायत के बाद गुप्त रूप से योजना बनाकर शिकायतकर्ता को ग्राम पंचायत भेजा गया था। रिश्तत की राशि लेते हुए सरपंच और उनके पति को पकड़ा गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास में जबलपुर के उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंट की।

भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी डटे सफाई कर्मचारी, 5 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी कामबंद की चेतावनी



मंदसौर। नगर पालिका परिषद मंदसौर के सफाई कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी चौराहा पर शुरू की अनिश्चितकालीन कर्मिक भूख हड़ताल सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। मांगों का निराकरण नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश बना हुआ है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ठोस और लिखित निर्णय नहीं होने पर 5 अक्टूबर से प्रदेशभर में सफाई कर्मचारी

कामबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना मार्शल कौम, नगरपालिका सफाई कर्मचारी एवं समस्त कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर संतोष कल्याणे ने 26 सितंबर से शुरू हुई भूख हड़ताल के दूसरे दिन ही प्रदेशव्यापी कामबंद हड़ताल की घोषणा की थी। सोमवार को तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि धरना स्थल पर मौजूद रहे।

कर्मचारियों ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उनकी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने, समय पर वेतन दिलाने तथा 100 पुरुष और 100 महिला सफाई कर्मचारियों को नई भर्ती सहित 15 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को समर्थन देने के लिए नीमच से कर्मचारी प्रतिनिधियों का मंडल भी धरना स्थल पर पहुंचा। सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने कामबंद हड़ताल के समर्थन में सहमति पत्र सौंपा। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच और म.प्र. दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित गैंगमैन एकता यूनियन (सीटू) सहित अन्य सामाजिक एवं श्रमिक संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 5 अक्टूबर से प्रदेशभर के सफाई कर्मचारी कामबंद रखेंगे। इसमें मंदसौर के सफाई कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। आंदोलनकारियों ने इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन और शासन की होने की बात कही। धरना स्थल पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, समाजजन तथा बड़ी संख्या में महिला-पुरुष सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।

शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : कलेक्टर

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के विभागवार निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर निराकरण संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सीएम हेल्ललाइन की शिकायतों की भी विभागवार समीक्षा कर शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने नगरीय निकायवार ट्रेडिंग ग्राउंड के क्रियायन की समीक्षा की। उन्होंने क्वालिटी सुग्रीगेशन तथा



आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां अभी से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। चिचोली के ट्रेडिंग ग्राउंड से संबंधित समस्या का भी शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कर उन्हें रियल टाइम निराकरण

की स्थिति में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में भी अपेक्षित प्रगति लाने को कहा। संबल योजना से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन की

समीक्षा करते हुए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। किसी योजना के बंद होने अथवा अपूर्ण रहने की स्थिति में संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय कर समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फ्लैग डे पर विभागों को दिए गए लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। 3 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर और 7 अक्टूबर को नगरीय निकायों में होगा सेवा सेतु अभियान कलेक्टर डॉ सोनवणे ने सेवा सेतु अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि अभियान के तहत 3 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर तथा 7 अक्टूबर को नगरीय निकायों में प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे।

हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़े में विद्यार्थियों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

बैतूल। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एवं हिन्दी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मोनाक्षी चौबे के संरक्षण, हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. अनीता सोनी के मार्गदर्शन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संयोजक प्रो. राकेश कुमार पवार के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। छात्रा भावना

सूर्यवंशी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना ने कार्यक्रम को जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एवं हिन्दी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मोनाक्षी चौबे के संरक्षण, हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. अनीता सोनी के मार्गदर्शन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संयोजक प्रो. राकेश कुमार पवार के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। छात्रा भावना

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

क्लासीफाईड विज्ञापन दरें

150/- रुपये प्रतिदिन 25 शब्दों तक

स्क्रीम

2 दिन के विज्ञापन पर 2 दिन अतिरिक्त प्रकाशन
5 दिन के विज्ञापन पर 10 दिन अतिरिक्त प्रकाशन
10 दिन के प्रकाशन पर 20 दिन अतिरिक्त प्रकाशन

राष्ट्रीय गरिमा समाचार पत्र में विज्ञापन देकर अपने व्यापार को दें नई उड़ान

सम्पर्क करें : 8602000710, 8602000703

मात्र 1500/- रुपये में पूरे एक माह चलानें

दिल्ली में दलित और आदिवासी सम्मान बैठक बुलाएगी आज कांग्रेस
नई दिल्ली। कांग्रेस ने कल मंगलवार 29 सितंबर को दिल्ली में दलित-आदिवासी सम्मान बैठक बुलाने की घोषणा की है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उतरखंड के हल्द्वानी दौर के बाद हुई कथित शुद्धिकरण घटना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के खिलाफ रहे हर अत्याचार तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

दैनिक

राष्ट्रीय



गरिमा

www.rashtriya garima.com

भोपाल, मंगलवार 29 सितम्बर 2026

चिराग पासवान को एनडीए की नीतियों का करना चाहिए विरोध: राजपूत
लखनऊ। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने चिराग पासवान के प्रयागराज युवा संपर्क अभियान, प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की बैठक और कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को अदालत से मिली सह्य पर प्रतिक्रिया दी। चिराग पासवान के प्रयागराज युवा संपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कह, हर राजनीतिक पार्टी को अपने धेन, वोटर्स और युवाओं से बात करने का अधिकार है।

चुनाव आयोग विवाद पर 30 सितंबर को दिल्ली में जुटेगा विपक्षी गठबंधन

विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की उठेगी मांग

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद के बीच विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। गठबंधन के घटक दल 30 सितंबर को दिल्ली में बैठक कर चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और विपक्ष की ओर से चलाए जाने वाले संयुक्त अभियान जैसे मुद्दे प्रमुख रहने की संभावना है।



रिपोर्टों के अनुसार, बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस

प्रमुख ममता बनर्जी ने भी विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर समन्वय की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस विषय पर चर्चा करने और विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर रणनीति बनाने की बात कही है। ममता बनर्जी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव एमए बेबी से भी बातचीत की है। इस घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से एक-दूसरे की विरोधी तृणमूल कांग्रेस और माकपा भी चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर साथ आती दिखाई दे रही हैं। माकपा महासचिव एमए बेबी ने विपक्षी दलों के बीच व्यापक लामबंदी की अपील की है। वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के महासचिव दीपांकर

भट्टाचार्य ने 30 सितंबर की बैठक को काफी समय से अपेक्षित बताया है और विपक्षी दलों के एक साथ आने की जरूरत पर जोर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डेरेक ओन्ग्रान ने कहा है कि चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे विपक्ष के प्रयासों के केंद्र में बने रहेंगे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित अन्य मांगों को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। इस बीच विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नए महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी भी कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सूर्यों के अनुसार, दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने के लिए

नोटिस तैयार किया जा रहा है। इसे कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के बाद संसद में पेश किए जाने की संभावना है। रिपोर्टों के मुताबिक, विपक्ष इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस दे चुका है। अप्रैल में लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए प्रस्तावों को संबंधित पीठासीन अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया था। विपक्ष अब नए घटनाक्रम और विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित उठाए गए सवालों के आधार पर नया नोटिस तैयार कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिनके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

साल 2022 से 2026 के बीच 111 सांसदों और विधायकों ने बदली पार्टी

29 नेता भाजपा में, 9 कांग्रेस में गए,नागालैंड में सबसे ज्यादा 32 मामले

नई दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच को एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 के बीच चुनाव जीतने के बाद कुल 111 सांसदों और विधायकों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बदली। इनमें 26 लोकसभा सदस्य,सात राज्यसभा सदस्य और 78 विधायक शामिल हैं। यह विश्लेषण इस अवधि में हुए चुनाव और उपचुनावों के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 111 मामलों में व्यक्तिगत तौर पर पार्टी बदलना, राजनीतिक दलों का विलय, इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव जीतना तथा अयोग्य ठहराए जाने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल होकर उपचुनाव जीतना शामिल है। एडीआर ने यह भी कहा है कि उपलब्ध आधिकारिक आंकड़े व्यवस्थित रूप से एक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण रिपोर्ट में सभी मामलों का शामिल होना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलकर



दूसरी पार्टियों में शामिल होने वाले नेताओं में सबसे अधिक 32 नेता नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) में गए। इसके बाद भाजपा में 29 और नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में 20 नेता शामिल हुए। कांग्रेस में नौ, शिवसेना में आठ, नेशनल पीपुल्स पार्टी में छह और अरुणाचल प्रदेश पीपुल्स पार्टी में चार नेता शामिल हुए। भाजपा में शामिल हुए 29 नेताओं में सात राज्यसभा सदस्य और 22 विधायक थे। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें गोवा के आठ कांग्रेस विधायक, गुजरात के चार कांग्रेस विधायक

पंजाब में आठ-आठ मामले सामने आए। कुल मिलाकर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी बदलने के मामले दर्ज किए गए। हालांकि, नागालैंड के 32 मामलों की प्रकृति अन्य मामलों से अलग है। एडीआर के अनुसार, ये मामले वर्ष 2025 में हुए राजनीतिक दलों के विलय से जुड़े हैं। इन 32 विधायकों में 25 पहले राखवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी (एनडीपीपी) के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और बाद में नागा पीपुल्स फ्रंट में शामिल हुए। इसलिए नागालैंड का आंकड़ा व्यक्तिगत दल-बदल के बजाय मुख्य रूप से राजनीतिक दल के विलय का परिणाम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन राजनीतिक दलों से नेताओं ने पार्टी बदली, उनमें राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी के 25, तृणमूल कांग्रेस के 20 और कांग्रेस के 19 नेता शामिल हैं। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति के नौ, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सात-सात, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह, जनता दल (यूनाइटेड) के पांच और नेशनल पीपुल्स पार्टी के चार नेताओं ने पार्टी बदली।

आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने परिवार को गाली दी,इसलिए थप्पड़ मारा : वर्मा

थप्पड़कांड पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह दी अपनी राफाई

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान युवक को थप्पड़ मारे जाने के मामले सफाई देते हुए आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आआपा) के विधायक जरनैल सिंह कमीशन न मिलने पर रात में बनी सड़क सुबह-सुबह उखाड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि आज निरीक्षण के दौरान आआपा कार्यकर्ता ने सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ उनके परिवार रको गालियां दीं। मंत्री प्रवेश साहिब ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विकासपुत्री रिंग रोड पर पिछले कई दिनों से सड़क बनाने का काम चल रहा है। स्थानीय विधायक जरनैल सिंह, पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों



पर दबाव डाल रहे थे कि वे उन्हें ठेकेदार से मिलवाएं और उनके लिए कमीशन का इंतजाम करें, वे काफी समय से यह मांग कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर करवा रहे हैं क्योंकि जरनैल सिंह को कोई कमीशन नहीं मिला इसलिए वे सुबह साइट पर जाते थे-रात में सड़क बनने के बाद उसे उखाड़ देते थे। फिर वे वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करते थे और दावा करते थे कि

भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज उस रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि वह खुद काम का निरीक्षण करना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि निरीक्षण के दौरान काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि यह सड़क 15 साल से नहीं बनी थी और डेढ़ दशक बाद आखिरकार इसका निर्माण हो रहा है। उन्होंने खुद जरनैल सिंह को तीन बार फोन किया और 45 मिनट तक उनका इंतजार किया। मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को साइट पर नहीं बुलाया था। उन्होंने कहा कि क्लब जरनैल सिंह आए तो वे अपने साथ उन कार्यकर्ताओं को लाए जिन्हें पहले ही बता दिया गया था और उन्होंने तुरंत बदतमीजी से व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब उनके एक कार्यकर्ता ने मेरे परिवार को गालियां देना शुरू किया, तो मैंने वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे कोई भी गुस्से में देता।

विदेशी नंबर से 25 करोड़ रूपए की फिरौती मांगने वाले का पर्दाफाश



छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आरोपी शोएब ड़ेवर को किया गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विदेशी मोबाइल नंबर से वाट्सऐप के माध्यम से 25 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को अमन साहू गिरोह से जुड़ा बताया था और प्रार्थी आनंदमल कुकरेजा, उनके पुत्र सहित परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना से संबंधित पांच आईफोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर 2026 को प्रार्थी आनंदमल कुकरेजा के मोबाइल फोन पर विदेशी मोबाइल नंबर से वाट्सऐप के माध्यम से धमकी भरे संदेश प्राप्त हुए थे। संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने स्वयं को अमन साहू गिरोह से संबंधित बताया और प्रार्थी से 25 करोड़ रुपये की फिरौती मांग की। रकम नहीं देने पर प्रार्थी, उनके पुत्र अजीत तथा परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करने की धमकी दी गई। साथ ही रायपुर और तेलीबांधा क्षेत्र में भी हत्या करवाने की बात कही गई। धमकी भरे संदेशों के बाद प्रार्थी ने मामले की शिकायत थाना तेलीबांधा में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 403/26 के तहत

भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4), 351(3) और 351(4) में मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले, पुलिस उपायुक्त (अपराध एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (मध्य जोन) तारकेश्वर पटेल के मार्गदर्शन में एंटी फ्राइड एवं साइबर इकाई तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। संयुक्त टीम ने प्रार्थी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की और धमकी भरे वाट्सऐप संदेशों, विदेशी मोबाइल नंबर, आरोपी द्वारा भेजे गए अन्य संदेशों और वीडियो से संबंधित जानकारी जुटाई। इसके बाद विदेशी नंबर समेत उससे जुड़े अन्य मोबाइल नंबरों और तकनीकी जानकारीयों का बारीकी से विश्लेषण किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल नंबरों की कड़ियों, संपर्कों और उपलब्ध डिजिटल जानकारी का आपस में मिलान किया।

BURGO
CONSTRUCTION

BURGO
CONSTRUCTION

WHERE QUALITY MEETS INNOVATION

✓ CONSTRUCTION

✓ RENOVATION

✓ DESIGNING

✓ CONSULTATION

✓ PLANNING

✓ MANAGEMENT

CALL NOW

+91-860-2000-710

WWW.BURGOCONSTRUCTION.COM

कंपनियों के लिए नई चुनौती

रूटो की आम छवि अमेरिका समर्थक की है, लेकिन हाल में उन्होंने चीन से संबंध मजबूत किए हैं। चीन का पहलू अफ्रीका में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए नई चुनौती बन कर उभरा है। बढ़ते राजनीतिक विरोध की चुनौती झेल रहे केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो का भारतीय कंपनी- टाटा केमिकल्स मगाडी को देश से निकालने का फैसला विवादास्पद है। समझा जाता है कि केन्या में विदेशी निवेशकों के प्रति फैल रही भावना को शांत करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। बहरहाल, यह निर्णय टाटा ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए तगड़ा झटका है। इससे विदेशों में निवेश कर रही हर भारतीय कंपनी को उचित सबक लेना चाहिए। केन्या के स्थानीय समुदायों में टाटा कंपनी के खिलाफ लंबे समय से असंतोष पनप रहा था। शिकायत थी कि लेक मगाडी के समृद्ध सोडा ऐश संसाधनों का इस्तेमाल तो खूब हुआ, लेकिन बुनियादी ढांचे या रोजगार के रूप में उस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। अब रूटो ने वादा किया है कि वे वहां ऐसी विदेशी कंपनी को ठेका देंगे, तो स्थानीय विकास के लिए भी निवेश करे। चर्चा है कि ये ठेके चीनी कंपनियों को दिए जाएंगे। रूटो की आम छवि अमेरिका समर्थक नेता की है, लेकिन हाल में उन्होंने चीन से संबंध मजबूत किए हैं। चीन का पहलू अफ्रीका में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए नई चुनौती बन कर उभरा है। जिस ढंग से टाटा कंपनी को निकालने का फैसला हुआ, वैसे कदमों से सामान्यतः सभी विदेशी निवेशकों में नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन चीनी कंपनियां अक्सर जोखिम उठाते हुए ऐसे हालात का लाभ उठाने को कोशिश करती हैं। साथ ही इस घटना ने उजागर किया है कि अफ्रीका में आई नई जन चेतना के बीच वहां कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए केवल कानून का पालन ही काफी नहीं रह गया है। बल्कि अब चुनौती स्थानीय समुदायों को संतुष्ट रखते हुए अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की है। इस सिलसिले में पर्यावरण संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन कर उभरा है। गुजरे डेढ़ दशक में अडानी ग्रुप, रिलायंस, जीएमआर, जिंदल, एस्सार आदि जैसी भारतीय कंपनियों को या तो कुछ देशों से निकाला गया है, या वहां उनके साथ हुए करार बाद में रद्द कर दिए गए। ऐसी घटनाओं से देश की छवि बिगड़ती है। भारतीय कंपनियों को इस बात ख्याल रखना चाहिए।

जब हुनर को मंच और अनुभव को अवसर मिलता है, तब बदलता है भविष्य

एल.डी. मानिकपुरी



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के हालिया निर्णय इसी सोच को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। एक ओर नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) की स्थापना होने से युवाओं को आधुनिक कौशल का मंच मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विभिन्न शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष किया जाना अनुभव और क्षमता को नए अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। सपनों को डिग्री के साथ हुनर भी चाहिए आज का युवा केवल शिक्षा नहीं, रोजगारपरक कौशल चाहता है। उद्योगों की बदलती जरूरतों के बीच ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का महत्व बढ़ गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्राम तेंदुवा में एनएसटीआई की स्थापना के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी।



छत्तीसगढ़ की पहचान लंबे समय तक ‘धान के कटोरे’ के रूप में रही है। खेतों में लहलहाती फसलें प्रदेश की समृद्धि की कहानी कहती हैं, लेकिन बदलते समय के साथ छत्तीसगढ़ ने विकास की अपनी यात्रा में नए आयाम जोड़े हैं। अब कृषि के साथ उद्योग, तकनीक के साथ कौशल और रोजगार के साथ उद्यमिता भी प्रदेश की नई पहचान बन रही है। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत प्रदेश के युवा और अनुभवी मानव संसाधन हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के हालिया निर्णय इसी सोच को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। एक ओर नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) की स्थापना होने से युवाओं को आधुनिक कौशल का मंच मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विभिन्न शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष किया जाना अनुभव और क्षमता को नए अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। सपनों को डिग्री के साथ हुनर भी चाहिए आज का युवा केवल शिक्षा नहीं, रोजगारपरक कौशल चाहता है। उद्योगों की बदलती जरूरतों के बीच ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का महत्व बढ़ गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्राम तेंदुवा में एनएसटीआई की स्थापना के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी। यहां दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में हर वर्ष करीब एक हजार तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों में लगभग तीन हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। हजारों युवाओं के सपनों से जुड़ा अवसर है। इससे कोई तकनीकी कौशल हासिल करेगा, कोई उद्योग से जुड़ेगा, तो



कोई अपना उद्यम शुरू कर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। कौशल से रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह एनएसटीआई की स्थापना होने से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। आज कौशल केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है। गांव और कस्बे के युवा को भी उद्यमशील बनने का अवसर मिलेगा। एक प्रशिक्षित युवा नौकरी तलाशने वाला बनने के साथ नौकरी देने वाला उद्यमी भी बन सकता है। यही कौशल से उद्यमिता और रोजगार से आत्मनिर्भरता की यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के युवाओं से अक्सर कहते हैं कि ऐसा कार्य करें जो युवाओं को रोजगार देने वाला बने, ताकि उनकी नई पहचान बन सके। उम्र बढ़ी तो अवसरों का दायरा भी बढ़ा अधिकतम आयु सीमा को 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय उन लोगों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है, जिनके पास अनुभव, कार्यकुशलता और जिम्मेदारियों का व्यावहारिक ज्ञान है। उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है और अनुभव किसी भी व्यवस्था की महत्वपूर्ण पूंजी है। वर्षों तक काम कर चुके लोगों ने

व्यवस्था को करीब से समझा है और चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे अनुभव का बेहतर उपयोग नई जिम्मेदारियों में किया जाना संस्थाओं को अधिक सक्षम बना सकता है। युवा ऊर्जा और अनुभवी हाथ साथ चलें विकास की मजबूत तस्वीर तब बनती है, जब युवा ऊर्जा और अनुभवी सोच साथ आती है। युवा नई तकनीक और नए विचार लाते हैं, जबकि अनुभवी वर्ग व्यावहारिक समझ और परिस्थितियों से निपटने का अनुभव देता है। एनएसटीआई युवाओं के हुनर को मंच देगा, तो आयु सीमा में वृद्धि अनुभवी वर्ग की क्षमता को अवसर। दोनों निर्णय मिलकर प्रदेश की मानव पूंजी को मजबूत करने की दिशा दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का भविष्य केवल उसकी प्राकृतिक संपदा से नहीं, बल्कि उसके लोगों की क्षमता से तय होगा। जब हुनर को मंच, अनुभव को अवसर और सपनों को सही दिशा मिलेगी, तब विकास आंकड़ों से निकलकर लोगों की जिंदगी में दिखाई देगा। यही नए छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, जहां कौशल से रोजगार, अनुभव से अवसर और अवसर से आत्मनिर्भरता की राह तैयार हो रही है। इसी तरह के निर्णयों से छत्तीसगढ़ सरकार सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेखक सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं।

एक स्वास्थ्य, एक भविष्य: सेहतमंद भविष्य के लिए आयुर्वेद

प्रतापराव जाधव

दुनिया अब सेहतमंद होने के मायने पर नए सिरे से सोच रही है। आज स्वास्थ्य-देखभाल का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है; बल्कि इसका मकसद बीमारियों को रोकना, तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना और ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है, जो बदलती जीवनशैली, पर्यावरण के दबाव और नई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर सके। इस बदलते परिदृश्य में, आयुर्वेद भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टि की पेशकश करता है। 11वें आयुर्वेद दिवस की थीम, सेहतमंद भविष्य के लिए आयुर्वेद और एक स्वास्थ्य, एक भविष्य का विज़न इस विचार को बहुत खूबसूरती से पेश करता है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य का कोई अलग-थलग अस्तित्व नहीं होता। लोगों, समुदायों, पशुओं और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। आयुर्वेद ने हमेशा बीमारी से बचाव, संतुलित जीवन, सही खान-पान, दैनिक दिनचर्या और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर बहुत जोर दिया है। ऐसे समय में जब जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ, उपापचय विकार, तनाव और दूसरी गैर-संक्रामक बीमारियाँ समाज पर बोझ बढ़ा रही हैं, ये सिद्धांत और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन आयुर्वेद को आगे ले जाने का मतलब सिर्फ पीछे मुड़कर देखना नहीं हो सकता। इसके भविष्य को शोध, साक्ष्यों, नवाचार और गुणवत्ता के जरिए आकार दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि आयुर्वेद से जुड़े ज्ञान का अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से हो और उसे ऐसे समाधानों में बदला जाए, जो आज की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करते हों। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने इस यात्रा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना; आयुर्वेद और अन्य आयुष प्रणालियों को एक मजबूत संस्थागत आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तब से, इसका दायरा संरक्षण और प्रचार-प्रसार से बढ़कर शोध, शिक्षा,



स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, गुणवत्ता आश्वासन, नवाचार और वैश्विक सहयोग तक विस्तृत हो गया है। स्वास्थ्य देखभाल को असल में मरीज़ की ज़रूरतों पर केंद्रित होना चाहिए। जहां उपचार उपयुक्त और साक्ष्य समर्थित हो, वहाँ विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियाँ एक-दूसरे की पूरक बन सकती हैं और स्वास्थ्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण में योगदान दे सकती हैं। जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष सेवाओं का एकीकरण और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार, रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य सेवा को ज़्यादा सुलभ बनाने के हमारे संकल्प को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत आयुर्वेद को दुनिया तक भी पहुँचा रहा है। आयुर्वेद दिवस के पिछले आयोजनों ने दिखाया है कि स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति भारत के नज़रिए को दुनिया भर में कैसा समर्थन मिल सकता है। आयुर्वेद दिवस ने भारत की स्वास्थ्य परंपराओं के लिए एक वैश्विक अवसर का निर्माण किया है और आयुर्वेद तेज़ी से कल्याण, रोकथाम और सतत स्वास्थ्य सेवा पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय बातचीत का हिस्सा बन रहा है। इस बढ़ती वैश्विक रुचि के साथ एक उत्तनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। आयुर्वेद को विश्वसनीय शोध, नैदानिक सबूतों, मजबूत गुणवत्ता मानकों और जिम्मेदार संचार का समर्थन मिलना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आयुष शैक्षिक विभाग, नैदानिक शोध और

विनियामक तालमेल की दिशा में किए जा रहे प्रयास भारत से बाहर आयुर्वेद के लिए एक मज़बूत इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इसकी वैश्विक पहुँच का विस्तार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि इस विकास के साथ भरोसा और वैज्ञानिक विश्वसनीयता भी जुड़ी हो। एक स्वास्थ्य, एक भविष्य का विज़न हमें अस्पतालों और दवाओं से आगे ले जाता है। एक स्वस्थ भविष्य हमारे पर्यावरण, हमारे खान-पान और उन प्राकृतिक संसाधनों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, जिन पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, औषधीय पौधे स्वास्थ्य सेवा को कृषि, आजीविका और जैव विविधता से जोड़ते हैं। उनकी स्थायी खेती से किसानों के लिए आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं और साथ ही कीमती प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी योगदान मिल सकता है। प्रौद्योगिकी भी एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। आज भारत के पास अपने व्यापक आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक शोध क्षमताओं, डिजिटल तकनीक, डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते उपायों के साथ जोड़ने का मौका है। यह संयोजन शोधकर्ताओं को पारंपरिक तरीकों का ज़्यादा सटीकता से अध्ययन करने और नवाचार के नए अवसरों को सामने लाने में मदद कर सकता है। फिर भी, सबसे

महत्वपूर्ण बदलाव लोगों के जीवन में आना चाहिए। आयुर्वेद दिवस को केवल साल में एक बार मनाया जाने वाला आयोजन बनकर नहीं रहना चाहिए। इसे हमारे घरों, स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली आधारित एक व्यापक अभियान को बढ़ावा देना चाहिए। हम क्या खाते हैं, हम कितने सक्रिय रहते हैं, हम तनाव का प्रबंधन कैसे करते हैं और हम अपने पर्यावरण के साथ कितनी जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, ये सभी हमारे समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस यात्रा में युवा पीढ़ी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद को सिर्फ भारत की विरासत के तौर पर ही नहीं, बल्कि शोध, नवाचार, उद्यमिता और स्वास्थ्य सेवा के ऐसे क्षेत्र के तौर पर पेश किया जाना चाहिए, जो भविष्य की चुनौतियों को हल करने में योगदान दे सकता हो। आज भारत ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक अनोखे संगम पर खड़ा है। हमारे पास इन ताकतों को एक साथ लाने का अवसर है, ताकि स्वास्थ्य सेवा का ऐसा तरीका विकसित किया जा सके, जो इलाज के साथ-साथ बीमारी से बचाव, बीमारी के प्रबंधन के साथ-साथ आरोग्यता और विकास के साथ-साथ स्थानिक को भी महत्व देता हो। आयुर्वेद का भविष्य अंततः इस बात से निर्धारित होगा कि हम इस पर कितना अच्छा शोध करते हैं, सबूतों के आधार पर इसे कितना मजबूत बनाते हैं, इसकी गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करते हैं और इसके फायदों को लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं। इसलिए, सेहतमंद भविष्य के लिए आयुर्वेद सिर्फ एक थीम नहीं है। यह सेहत की संस्कृति बनाने का एक आह्वान है — ऐसी संस्कृति, जो लोगों को सशक्त बनाती हो, समुदायों को मजबूत करती हो और उस पर्यावरण का सम्मान करती हो, जिसे हम सभी साझा करते हैं। जब हम 11वाँ आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, तो आइए एक स्वास्थ्य, एक भविष्य के विज़न को आगे बढ़ाएँ और एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ दुनिया की दिशा में मिलकर काम करें। एक स्वास्थ्य, एक भविष्य। सभी के लिए सेहतमंद भविष्य। (लेखक केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं)

राशिफल

मेष राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे , जिसमें आपको किसी करीबी की सहायता मिलेगी। आज आपकी काम में रुचि बनी रहेगी और हलैक्स मस्यूस करने के लिए मनोरंजन संबंधी योजनाएं भी बन सकती है। आज आप किसी काम को बहुत ही शांत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलनी तय है।

वृष राशि : आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप किसी भी काम को बहुत ही सावधानीपूर्वक करेंगे तो अच्छा होगा। आज आप अपनी योग्यता और क्षमता से काम को आसानी से कर लेंगे , इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बन रही है, तो वास्तु समेत नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा।

मिथुन राशि : आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज आप भीड़ से अलग हटकर कुछ नया करने का प्रयास करेंगे , जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपकी रुचि संगीत में रहेगी , आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म भी कर सकते हैं। ऑफिस में आपको कुछ नए कामों की जिम्मेदारी मिलेगी, जिसको आप सफलतापूर्वक पूरा भी कर लेंगे।

कर्क राशि : आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और इस उचित समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे। व्यावसायिक पार्टियों के साथ रिश्ते मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे।

सिंह राशि : आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आप व्यवसाय को विस्तार देने के लिए ऑफिस में मीटिंग कर सकते हैं। आज आपके घर में लंबे समय बाद किसी रिश्तेदार का आगमन होगा , जिससे आपसी गलफजलियां दूर होंगी। आज बच्चों के साथ उनके क्रियाकलापों में रुचि लेना और सहयोग करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत बनाएगा।

कन्या राशि : आज का दिन आपके लिए रोज की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज बच्चों की शिक्षा और करियर से संबंधित भी काम हो सकता है। आज बिजनेस में आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और आज आप सिर्फ अपने काम की कालिंदी को अधिक बेहतर बनाने में ध्यान देंगे। आज ऑफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

तुला राशि : आज का दिन आपके लिए फेबरेखल रहने वाला है। आज आपको व्यापार में अच्छ धन लाभ होगा लेकिन आज खर्च की अधिकता रह सकती है। आज समय का उचित सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलने के योग है। आज आप व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कार्यों में भी रुचि लेंगे।

वृश्चिक राशि : आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आप दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद की मदद करके करेंगे , जिससे आपको पूरा दिन सकारात्मक परिणाम मिलते ही रहेंगे। आज आप अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें अन्यथा किसी को बुरा लग सकता है। आज आप अपने कर्मचारियों का उत्साह वर्धन करेंगे।

धनु राशि : आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप कार्यक्षेत्र में एक नया और कीर्तिमान इतिलास रकचर दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगे। आज आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग है , जिससे आपकी आय और पद दोनों ही लाभदायक रहेंगे।

मकर राशि : आज का दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आप ऑफिशियल काम के साथ-साथ अपने निजी कार्यों को भी समय देंगे, जिससे आपको शारीरिक थकान का अहसास हो सकता है। आज राजनीतिक और अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा देगी।

कुंभ राशि : आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप अपनी योजनाओं को प्रभावशील बनाने के लिए कुछ लेस और जरूरी कदम उठाएंगे। आज अचानक ही आपको कहीं से सहयोग और उचित सलाह भी हासिल होगी। इस राशि की महिलाएं आज किसी काम की शुरुआत कर सकती है , जिसमें उन्हें जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

मीन राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, इससे आपके कार्य सफल होंगे। आज आपके परिवार का बहोत खुशदुखी रहेगा और परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। आज आप व्यवसाय में मामूली परिवर्तन करेंगे , जिससे काम की गुणवत्ता अच्छी बनेगी।

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी - प्रक्रिया, नियम और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स



आजकल, जहाँ अलग-अलग धर्म और जाति में शादी करने के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग आज भी अपनी पसंद के लड़के या लड़की से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर उनके घर वालों का दबाव होता है। इस समस्या का हल अंतरधार्मिक विवाह (स्पेशल मैरिज एक्ट) में है। यह कानून अलग-अलग धर्मों या जातियों के लोगों को बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज के शादी करने की आज़ादी देता है। इस एक्ट के तहत शादी करने से ना केवल आपको कानूनी सुरक्षा दी जाती है, बल्कि आप अपनी पसंद के साथी के साथ बिना किसी डर के विवाह कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको इस एक्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है? विशेष विवाह एक्ट के तहत शादी करने की प्रक्रिया - नियम, शर्तें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट और फीस? हिंदू-मुस्लिम लड़की-लड़की की शादी अंतरधार्मिक विवाह कानून के तहत कैसे होती है?

विशेष विवाह एक्ट, 1954 क्या है?
स्पेशल मैरिज एक्ट हिंदी में

जब दो लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनका धर्म या जाति अलग होता है, तो उन्हें अपने परिवार, समाज के लोगों और धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही मुश्किलों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट (1954) कहा जाता है। यह कानून हिंदू-मुस्लिम या किसी भी धर्म के बीच अंतरधार्मिक विवाह करने की आजादी देता है। जो लोग धर्म या जाति की परवाह किए बिना एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और बिना कोई धार्मिक रस्म के शादी कर सकते हैं।

स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कैसे होती है?

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादी को हम

लॉ मैरिज या कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है। शादी की इस प्रक्रिया में न तो कोई पंडित चाहिए, न मौलवी, न चर्च की जरूरत होती है। बस दुल्हा-दुल्हन को मैरिज रजिस्ट्रार के सामने कानूनी नियमों के अनुसार शादी करनी होती है।

यह कानून किन लोगों के लिए है?

खास मैरिज एक्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अलग-अलग धर्म या जाति से होने के बावजूद आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं। आइये विस्तार से जानते हैं-

- अलग-अलग धर्म के जोड़े- जैसे हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और ईसाई, सिख और बौद्ध आदि। यह कानून किसी भी धर्म के लोगों को बिना धर्म बदले शादी करने की सुविधा देता है।
- अलग-अलग जाति के जोड़े (अंतर-जातीय जोड़े)= अगर लड़का-लड़की अलग जाति के हैं और वे शादी करना चाहते हैं, तो यह कानून उनकी मदद करता है।3. विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक (NRIs): अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में रह रहा है और किसी भारतीय या विदेशी से शादी करना चाहता है, तो यह कानून उनके लिए भी लागू होता है।

विशेष विवाह एक्ट के तहत शादी के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं?

इस कानून के तहत शादी करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है-

- लड़का कम से कम 21 साल का हो
- लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- दोनों की मर्जी से शादी हो रही हो
- दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों
- दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा न हो
- दुल्हा और दुल्हन रिश्ते ना हों, जैसे कि भाई-बहन, मामा-भांजी, आदि।

स्पेशल मैरिज एक्ट (अंतरधार्मिक विवाह) की क्या विशेषता है?

विशेष विवाह अधिनियम के इस कानून की खास बात यह है, कि इसमें धर्म नहीं देखा जाता सिर्फ लड़का-लड़की को सहमति देखी जाती है, और इसमें धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। यह विवाह सरकारी मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज के सीधे इस कानून के अनुसार होती है। यह शादी पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होती है

स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत शादी करने की प्रक्रिया क्या है?

भारत में विशेष विवाह अधिनियम के तहत हिंदू-मुस्लिम या किसी भी धर्म के बीच अंतरधार्मिक विवाह कर सकते हैं। आइये सरल भाषा में जानते हैं, कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की पूरी प्रक्रिया क्या है-

- शादी का इरादा बताना (नोटिस देना) सबसे पहला कदम है शादी का नोटिस देना। लड़का और लड़की को शादी से कम से कम 30 दिन पहले अपने शादीशुदा मैरिज ऑफिसर के पास जाना होता है। इसके बाद वहां पर दोनों को एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें उन्हें अपना नाम, उम्र, पता, काम, धर्म आदि की जानकारी भरनी होती है। यह फॉर्म जमा करने के बाद विवाह अधिकारी इस नोटिस को अपने ऑफिस की दीवार पर चिपका देता है, ताकि अगर किसी को इस शादी पर कोई कानूनी आपत्ति हो, तो वह 30 दिन के अंदर बता सके।
- नोटिस देने के बाद 30 दिन की प्रतीक्षा और आपत्ति नोटिस चिपकाने के बाद लड़का और लड़की दोनों को शादी के लिए 30 दिन तक इंतजार करना होता है। इन 30 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज (ऑब्जेक्शन लॉज्ड) करा सकता है, जैसे कि अगर लड़का लड़की में से किसी की पहले से शादी हो चुकी हो या उम्र 18/21 से कम हो। अगर कोई आपत्ति आती है, तो अधिकारी उसकी जांच करता है। अगर आपत्ति सही नहीं निकलती या कोई आपत्ति आती ही नहीं है, तो शादी की अनुमति मिल जाती है।
- शादी का रजिस्ट्रेशन अब बारी आती है शादी को कानूनी रूप से पूरा करने की। 30 दिन पूरे होने के बाद, लड़का और लड़की को अपने 3 गवाहों के साथ फिर से विवाह अधिकारी के पास जाना होता है। वहां पर सभी की पहचान की जांच की जाती है और फिर शादी की रस्म पूरी होती है। इस शादी में कोई धार्मिक रीति नहीं होती बस दोनों पक्ष मैरिज ऑफिसर के सामने कहते हैं कि वे एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं।
- विवाह प्रमाणपत्र मिलना (मैरिज सर्टिफिकेट जारी होना) शादी हो जाने के बाद, विवाह अधिकारी एक मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है। यह प्रमाणपत्र कभी-कभी उसी दिन मिल जाता है या फिर 2-3 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। यह प्रमाणपत्र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही साबित करता है कि शादी कानून के अनुसार और वैध रूप से हुई है। इसे आप पासपोर्ट, नामांकन, बैंक, संपत्ति के कामों या अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

शादी के लिए किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है?

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना शादी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। आइये उन सभी काम के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए ज़रूरी होते हैं।

- पहचान पत्र
- आधार कार्ड



- पासपोर्ट
 - वोटर ID कार्ड
 - उम्र प्रमाण पत्र
- शादी के लिए दोनों बेटों की उम्र का प्रमाण होना ज़रूरी है, जिसके लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है, जन्म प्रमाण पत्र, या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र (10th मार्कशीट)
- निवास प्रमाण पत्र
 - घर का प्रमाण पत्र (जैसे, बिजली का बिल, पानी का बिल या रेंट एग्रीमेंट)
 - आधार कार्ड में पता
 - पासपोर्ट साइज फोटो (पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ) शादी के आवेदन में हर व्यक्ति को 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होती है।
 - अविवाहित होने का शपथ पत्र इस शपथ पत्र में यह बताया जाता है कि आपकी पहले किसी से शादी नहीं हुई है, यानी आप अविवाहित हैं।
 - गवाहों के पहचान पत्र शादी के दौरान 3 गवाहों (गवाहों) की जरूरत होती है। इन गवाहों के पहचान पत्रों की जानकारी भी जमा करनी होती है। गवाहों के दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं-

- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड

विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने में खर्च - फीस और अन्य खर्च

विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने में कुछ खर्च होते हैं, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इन खर्चों में कुछ फीस अलग-अलग राज्य के हिसाब से बदल सकती है, आइये विस्तार से जानते हैं-

- नोटिस फीस जब आप विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी का नोटिस देते हैं, तो इसके लिए 100 से 150 तक फीस होती है। यह राशि राज्य के हिसाब से

- बदल सकती है।
- मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस आपकी शादी को कानूनी रूप से रजिस्टर करने के लिए आपको 500 से 1000 तक फीस चुकानी होती है। यह फीस भी राज्य और जिले के हिसाब से अलग हो सकती है।
- शपथ पत्र और दस्तावेज बनवाने का फीस शादी के लिए अविवाहित होने का शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए आपको 500 से 1500 तक का खर्च आ सकता है।
- वकील की मदद यदि आप वकील की मदद लेते हैं, तो इसके लिए अलग से 2000 से 5000 तक फीस लग सकती है। वकील की फीस उनके अनुभव और काम के हिसाब से अलग हो सकती है।

क्या हिंदू मुस्लिम लड़का-लड़की की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से हो सकती है?

हां, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू-मुस्लिम शादी हो सकती है। यह कानून विशेष रूप से अलग-अलग धर्मों के लोगों के विवाह के लिए ही बनाया गया है, यानी इस कानून के तहत किसी भी धर्म के दो व्यक्ति विवाह कर सकते हैं, चाहे उनका धर्म अलग-अलग क्यों न हो।

स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस देना क्यों जरूरी है?

विशेष विवाह अधिनियम के कानून के अनुसार, शादी से पहले 30 दिन का नोटिस देना ज़रूरी होता है। यह नोटिस किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का मौका भी देता है। अगर किसी को यह लगता है कि शादी में कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि गलत पहचान, धोखा या दबाव डाला जा रहा है, तो वे इसका विरोध कर सकते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

निष्कर्ष : स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान, सुरक्षित और कानूनी होती है। यह कानून उन सभी लोगों को बराबर का हक देता है जो सिर्फ प्यार और समझदारी के आधार पर विवाह करना चाहते हैं।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) क्या होता है - नियुक्ति, शक्तियां, अधिकार और कार्य

भारत में लोगों को न्याय दिलाने का सबसे बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट में एक सबसे बड़ा और अहम पद होता है जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायाधीश) कहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े कई फैसले और खबरें सामने आती रहती हैं। कभी वे किसी ज़रूरी मुद्दे पर खुद से केस शुरू कर देते हैं, तो कभी सरकार या समाज से जुड़ी बड़ी बातें कहते हैं। इससे यह समझ आता है कि उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस लेख में हम आपको इस महत्वपूर्ण पद के बारे में सभी जानकारी सरल भाषा में देंगे, कि CJI का पूरा नाम और मतलब क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश कैसे बनते हैं - योग्यता और नियुक्ति की प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के कार्य, शक्तियां और अधिकार।

(भारत के मुख्य न्यायाधीश) कौन होते हैं?

भारत के मुख्य न्यायाधीश देश और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश (जज) होते हैं। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुखिया (CJI) भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत (कोर्ट) होती है, इसलिए इसके मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के ऊपर देश के कानून और न्याय व्यवस्था (लॉ एंड जस्टिस सिस्टम) को सही तरीके से चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्य और जिम्मेदारियां क्या हैं?

भारत के मुख्य न्यायाधीश का काम सिर्फ फैसला सुनाना नहीं, बल्कि पूरे कोर्ट को सही तरीके से चलाना भी होता है। आइए आसान शब्दों में विस्तार से जानते हैं कि (CJI) क्या-क्या काम करते हैं :

- सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति करना : सुप्रीम कोर्ट के मुखिया यानी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) के कामकाज (फंक्शनिंग) को संभालते हैं।
- नए जजों की नियुक्ति (अपॉइंटमेंट) में मदद : जब सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के लिए नए जजों की जरूरत होती है, तो छद्म इस बारे में सुझाव (सुझाव) देते हैं। वे यह देखते हैं कि कौन से जज जस्टिस के काम के लिए अच्छे और योग्य हैं, और उनकी सलाह से राष्ट्रपति और सरकार नए जजों की नियुक्ति करते हैं।
- मामलों की सुनवाई का आरोप : मुख्य न्यायाधीश ये तय करते हैं कि कौन-से मामले कब सुनाए जाएंगे और उन्हें कितने न्यायाधीश (जज) देखेंगे। इसका मतलब है कि वे कोर्ट का काम ठीक तरह से चलते रहे इस बात का ध्यान रखते हैं ताकि सभी मामले समय पर निपटाए और कोई देरी न हो।
- सरकार और राष्ट्रपति को सलाह देना : जब भी सरकार या राष्ट्रपति को किसी कानून से जुड़ा कोई बड़ा सवाल या दिक्कत होती है, जैसे कि कोई नया नियम बनाना हो या कोई कानून सही है या नहीं, तो वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछे जाते हैं। जिससे सरकार और राष्ट्रपति (सरकार या राष्ट्रपति) सही फैसला ले समझते हैं।
- कोर्ट की व्यवस्था देखना : मुख्य न्यायाधीश इस बात का ध्यान रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही तरीके से चले। वे देखते हैं कि कोर्ट के कर्मचारी (कोर्ट स्टाफ) अपना काम ठीक से करें, कोर्ट के नियम (कोर्ट रूल्स) का पालन हो।
- न्याय का सही फैसला सुनाना : सुप्रीम कोर्ट के मुखिया का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है जैसे हर मामले में सही और ईमानदार फैसला देना।



इसका मतलब है कि वे ध्यान से सभी बातें सुनते हैं और सही कानून के अनुसार फैसला करते हैं ताकि हर व्यक्ति को उसका सही हक मिले।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति कैसे होती है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति संविधान के अनुसार बहुत ही खास तरीके से होती है। इसके लिए कुछ नियमों के साथ एक प्रक्रिया होती है, जिसके अनुसार ही ये फैसला लिया जाता है। आइये इसे विस्तार से जानते हैं :

कौन करता है नियुक्ति : भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन वह यह फैसला अकेले नहीं करते। इसके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े यानी सबसे अनुभवी जजों से सलाह लेते हैं। ताकि जो जज सबसे योग्य और अनुभवी हो, उसे ही यह जिम्मेदारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा समय तक काम करने वाले जज को ही सुप्रीम कोर्ट का मुखिया बनाया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?

भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कुछ खास नियम और योग्यताएं ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति मुख्य

न्यायाधीश बने, वह पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए। मतलब, वह पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में न्याय का काम कर रहे हो। आइये इसे सरल भाषा में समझते है :-

- भारत का नागरिक होना : सबसे पहला नियम यह है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही, वे या तो सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च में कम से कम 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो।
- जज ना होने पर : अगर कोई व्यक्ति जज नहीं है, तो भी वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसने कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में काम किया होना चाहिए। यानी उनके द्वारा कानून का अच्छा ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया गया होना चाहिए।
- 65 साल की उम्र तक : 65 साल की उम्र होने पर मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होना पड़ता है।

CJI और कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है?

भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और दूसरे बड़े जजों की नियुक्ति एक खास तरीके से होती है। इस तरीके को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

कॉलेजियम का मतलब होता है - एक समूह या टीम। इस टीम में सुप्रीम कोर्ट के कुछ सबसे बड़े और अनुभवी जज होते हैं। यही टीम नए जजों को चुनती है।

कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है?

सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के तीन सबसे बड़े जज सामने आते हैं कि कौन जज बनना चाहिए। जजों की योग्यता, अनुभव और काम को देखकर सही लोगों का योगदान होता है। फिर ये नाम सरकार और राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं।

सीजेआई और राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और राष्ट्रपति के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। ये दोनों मिलकर देश के कानून और विचारधारा को सही ढंग से बनाने में मदद करते हैं। इसे आसान भाषा में समझें :

संवैधानिक समस्या में मदद : अगर देश में कोई बड़ी कानूनी समस्या (कानूनी परेशानी) आती है, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सही रास्ता सुझते हैं। सरल भाषा में कहें तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सलाहकार (राष्ट्रपति के सलाहकार) होते हैं। राष्ट्रपति जब कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच रहे हों कि क्या सही होगा, तो वे सीजेआई से मदद लेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने दुकराया 7 दिवसीय युद्धविराम प्रस्ताव, हॉर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलकर रखा ट्रंप स्ट्रेट

वाशिंगटन/तेहरान,। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीतिक गतिरोध और गहरा गया है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें अमेरिका की कुछ शर्तें पूरी होने पर सात दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और परमाणु वार्ता बहाल करने की बात कही गई थी। इसके कुछ ही समय बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रूथ सोशल’ पर हॉर्मुज जलडमरूमध्य का एक नक्शा साझा किया, जिसमें इस रणनीतिक जलमार्ग को ‘ट्रंप स्ट्रेट’ के नाम से दर्शाया गया। हालांकि, इससे जलडमरूमध्य का आधिकारिक नाम नहीं बदला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान



संवाददाताओं को बताया था कि तेहरान ने अमेरिका के सामने युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए एक स्पष्ट योजना रखी है। उनके अनुसार, यदि अमेरिका प्रस्ताव में रखी गई

शर्तों को पूरा करता है तो ईरान सात दिनों के भीतर जलडमरूमध्य खोल सकता है और सामान्य समुद्री आवाजाही बहाल की जा सकती है। साथ ही दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत भी

फिर शुरू हो सकती है। ईरान की ओर से रखे गए प्रस्ताव में अमेरिका से उसके बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने और युद्धविराम का पालन करने की मांग की गई है। प्रस्ताव के तहत परमाणु मुद्दे पर रुकी हुई बातचीत को भी फिर शुरू करने की बात कही गई है। ईरानी विदेश मंत्री के अनुसार, यह प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिकी पक्ष तक पहुंचाया गया था। अराघची ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के सामने एक ठोस योजना रख दी है और अब अगला कदम वाशिंगटन को उठाना है। ईरान का कहना है कि वह कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव को कमी जरूरी होगी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप

को संदेह है कि ईरान उनकी कठोर शर्तों को स्वीकार करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि तेहरान मौजूदा आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए समझौते की कोशिश कर रहा है। ‘द वाल स्ट्रीट जर्नल’ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने अपने सलाहकारों से नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान के खिलाफ मंत्री कार्रवाई फिर शुरू होने की संभावना पर चर्चा की है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ ऐसा समझौता होना चाहिए, जिससे उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत में अब तक कोई स्थायी सहमति नहीं बन सकी है। ईरान के प्रस्ताव को टुकराए जाने की खबरों के बीच ट्रंप ने ‘ट्रूथ सोशल’ पर हॉर्मुज जलडमरूमध्य का नक्शा साझा किया।



लेबनान की राजधानी बेरुत में हिजबुल्लाह समर्थकों की भीड़। समर्थक हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या की दूसरी बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

रूस के एमसी-21 विमानों की विदेशी डिलीवरी 2032 के बाद होगी : निर्माता

इरकुत्स्क। रूस के एमसी-21 यात्री विमानों की दूसरे देशों को डिलीवरी वर्ष 2032 के बाद शुरू होगी। विमान निर्माता कंपनी इरकुत्स्क एविएशन ने कहा है कि कंपनी की उत्पादन क्षमता वर्ष 2032 तक पूरी तरह प्रतिबद्ध हो चुकी है। ऐसे में विदेशी बाजार के लिए कोई भी संभावित समझौता 2032 के बाद की अवधि के लिए होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन फिलहाल ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। उनके अनुसार, अतिरिक्त क्षमता तैयार करने और उसे बनाए रखने पर काफी खर्च आएगा तथा मांग में भविष्य में कमी आने की स्थिति में यह कंपनी के लिए चुनौती बन सकती है।

नेपाल के सप्तरी में बाढ़ का कहर, 500 घर डूबे; 2 हजार से अधिक लोग प्रभावित

काठमांडू। पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नेपाल के सप्तरी जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका और तिलाठी कोइलाडी गांवपालिका में बाढ़ का पानी घुसने से करीब 500 घर डूब गए हैं। बाढ़ के कारण दो हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 5, 7, 12 और 13 की बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसने से 483 घर डूब गए। वहीं, तिलाठी कोइलाडी गांवपालिका के वार्ड नंबर 4 और 5 में 17 घर जलमग्न हुए हैं। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका के प्रमुख वीरेन्द्र माझी ने बताया कि शुक्रवार रात सप्तकोशी नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल सुबह और शाम दो वक्त के भोजन की व्यवस्था की गई है। पानी का स्तर कुछ कम होने के बाद प्रभावित परिवारों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

कालीगंडकी नदी में भीषण बाढ़, स्यांगजा-गुल्मी को जोड़ने वाला पुल बहा

काठमांडू। नेपाल में कालीगंडकी नदी के तेज बहाव में स्यांगजा के मिर्मी और गुल्मी के हर्मिचौर को जोड़ने वाला पुल बह गया। यह पुल मिर्मी डैम साइड से नीचे स्थित था। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कालीगंडकी ‘ए’ जलविद्युत केंद्र में कार्यरत विष्णुप्रसाद न्यौपाने ने बताया कि कालीगंडकी ‘ए’ जलविद्युत परियोजना के डैम साइट पर पानी का बहाव बढ़ने के बाद पुल बाढ़ की चपेट में आ गया। गुल्मी के पुलिस प्रमुख एसपी भीम किरण बोगटी ने भी पुल के बहने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह बेली ब्रिज था, जिससे चार पहिया वाहन आवागमन करते थे।

संयुक्त राष्ट्र में शहबाज शरीफ ने भारत-पाक संघर्ष और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया



न्यूयॉर्क। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शुक्रवार को अपने संबोधन के दौरान मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय उनके हस्तक्षेप से दोनों परमाणु-संपन्न देशों के बीच तनाव को और बढ़ने से रोकने में मदद मिली। शरीफ ने कहा कि चार दिनों तक चल सैन्य टकराव के दौरान स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी और दोनों देश व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे। शरीफ ने कहा कि दक्षिण एशिया को दोबारा ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए, जहां सैन्य तनाव बड़े युद्ध का रूप ले ले। उन्होंने मई 2025

के संघर्ष का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत उठाया गया कदम बताया और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नेतृत्व की सराहना की। शरीफ ने अपने संबोधन में मई 2025 के सैन्य टकराव को भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के रूप में पेश किया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया था। दूसरी ओर, भारत मई 2025 की कार्रवाई को पहलगाम आतंकी हमले के बाद की कार्रवाई के रूप में बताता रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी।

पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा को हिरासत में लेने और रिहा करने पर नेपाल की संसद में सवाल

काठमांडू। नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा को हिरासत में लेने और बाद में रिहा किए जाने के मामले को लेकर संसद में सवाल उठाए गए हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य सचेतक युवराज दुलाल, एमाले के मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महार और श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद ध्रुवराज राई समेत अन्य सांसदों ने यह मुद्दा उठाया। मुख्य सचेतक दुलाल ने कहा बिना गिरफ्तारी वारंट और बिना किसी कारण के सरकार ने एक बार फिर कानून्विहीन राज्य का उदाहरण पेश किया है। आधी रात में एक नया तमाशा दिखाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि देश कानून के शासन के तहत आगे बढ़ रहा है या कानून्विहीन स्थिति की ओर। यदि किसी से सुरक्षा को खतरा है तो क्या खतरा पैदा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या किसी और को? यूएमएल के मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महार ने कहा, जिस तरह गुंडागर्दी

और अपहरण की शैली में उन्हें गिरफ्तार किया गया, वह राज्य के आतंक का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आपत्ति जताई कि राणा को इस तरह हिरासत में लिया गया और रिहा किया गया, मानो मैं ही राज्य हूं। श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद ध्रुवराज राई ने भरत दाहाल और चोलेन्द्र शमशेर राणा की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से जवाब मांगा। सांसद राई ने इसी मामले को पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणा को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने और फिर रिहा करने की घटना से जोड़ते हुए सरकार से सवाल किया।श्रम संस्कृति पार्टी ने इन घटनाओं को लेकर प्रधामंत्री बालेन्द्र शाह से स्वयं जवाब देने की मांग की है। सांसद ध्रुवराज राई ने कहा, एक तरफ भारत दाहाल को गिरफ्तार किया जाता है और फिर रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद चोलेन्द्रशमशेर को उठाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी, कई तालिबान लड़के मारे गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान-अफगान सीमा के पास गुलिस्तान सेक्टर में अफगान तालिबान लड़ाकों के हमले की कोशिश को विफल कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी जवाबी कार्रवाई में कई तालिबान लड़ाके मारे गए। सीमा पर गोलीबारी शुरू-रुक कर जारी है। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाके में हुई आक्रामकता की कोशिश का तुरंत जवाब दिया और अफगान तालिबान लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल सीमा पर पूरी तरह सतर्क और चौकस हैं। सूचना मंत्री अताउल्लाह तारार ने कहा कि यह घटनाक्रम तब हुआ जब पाकिस्तान ने इस सप्ताह की शुरुआत में तालिबान शासन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों की कोशिश को हरा दिया। अफगानिस्तान में 10 जगहों पर सटीक हवाई और ड्रोन हमले किए। इससे पहले अफगानिस्तान से देश के हवाई क्षेत्र में घुसने के बाद पाकिस्तान ने आठ ड्रोन मार गिराए।

संक्षिप्त समाचार

कनाडा में नाजी सहयोगियों से जुड़े दस्तावेज

सार्वजनिक करने की मांग बढ़ी : रूसी राजदूत

वाशिंगटन। कनाडा में इतिहासकारों, पत्रकारों और नागरिक संगठनों की ओर से उन नाजियों और उनके सहयोगियों से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग तेज हो रही है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कनाडा में शरण ली थी। ओटावा में रूस के राजदूत ओलेग स्ट्रेपानोव ने यह दावा किया है। रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती से बातचीत में स्ट्रेपानोव ने कहा कि इतिहासकारों, पत्रकारों और यहूदी संगठनों का एक वर्ग कनाडा सरकार पर संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने और देश के अतीत का ईमानदारी से आकलन करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि, उनके अनुसार कनाडाई अधिकारी इस मामले में टाल-मटोल कर रहे हैं। स्ट्रेपानोव ने कनाडाई संसद में पूर्व वाफेन-एसएस गैलिंगज़ियन डिवीजन के सैनिक यारोस्लाव हुंका को सम्मानित किए जाने से जुड़े विवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस घटना पर हुई प्रतिक्रिया से पता चला कि कनाडा में इस तरह के मामलों को लेकर व्यापक स्तर पर आपत्ति है। हुंका को सितंबर 2023 में कनाडाई संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में तत्कालीन स्पीकर एंथनी रोटा ने सम्मानित किया था। बाद में यह सामने आने के बाद कि हुंका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाफेन-यसएस गैलिंगज़ियन डिवीजन में सेवा की थी, इस घटना पर कनाडा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई। रोटा ने बाद में स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। स्ट्रेपानोव ने यह भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी की वाफेन-एसएस गैलिंगज़ियन डिवीजन में हुंका की सेवा का इतिहास गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने रूसी जांच समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर बारिज़किन के उस दावे का भी उल्लेख किया, जिसमें हुंका और उसके साथियों पर कम से कम 500 सोवियत नागरिकों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

बालेन्द्र शाह की संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस से मुलाकात, आपदा और जलवायु मुद्दे पर की चर्चा

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री शाह ने महासभा की संबोधित करने से पहले स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (नेपाली समयानुसार शुक्रवार सुबह 4:15 बजे) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव गुटेरेस से मुलाकात की। गुटेरेस ने भोटेकोशी आपदा में हुई जन-धन की क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जलवायु से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र नेपाल के साथ एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने नेपाली प्रतिनिधिमंडल में शामिल युवाओं की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार, गुटेरेस ने वर्ष 1978 में पर्यटक के रूप में नेपाल आने की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी नेपाल की मदद जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री शाह ने नेपाल के प्रति गुटेरेस के समर्थन और सद्भावना के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। शाह ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से नेपाल को भारी नुकसान हुआ है और हिमतालों के फटने का जोखिम अभी भी काफी अधिक है। बैठक में नदी किनारे रहने वाले लोगों के पुनर्वास और हरित पुनर्निर्माण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, अतिक्रम विकसित देशों की सूची से नेपाल के नियोजित स्तरोन्नयन की समयसीमा बढ़ाने के लिए समर्थन जुटाने के विषय पर भी बातचीत हुई।

एआईआईबी अध्यक्ष से मिले नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, निवेश बढ़ाने का आग्रह

काठमांडू। एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दोहा पहुंचे नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने बैंक के अध्यक्ष जू जियायी से मुलाकात की। दोनों के बीच नेपाल में बैंक के निवेश और प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में वित्त मंत्री वाग्ले ने नेपाल में एआईआईबी के निवेश का विस्तार करने, प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण में सहयोग करने और रियायती वित्तीय सुविधा तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक के दौरान वित्त मंत्री वाग्ले ने एआईआईबी अध्यक्ष जू जियायी को 2026 के भीतर नेपाल आने का निर्मंत्रण भी दिया। एआईआईबी अध्यक्ष जू जियायी ने नेपाल में आई हालिया विनाशकारी बाढ़ से नेपाल में हुई जन-धन की क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आपदा के बाद लचीले और टिकाऊ पुनर्निर्माण के लिए बैंक की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। एआईआईबी अध्यक्ष ने नेपाल के आर्थिक विकास में निरंतर सहयोग की बैंक की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि बैंक के प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्पेशलाइज्ड फंड के माध्यम से परियोजनाओं की तैयारी के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस विशेष फंड के तहत मिलने वाले अनुदान का उपयोग करके नेपाल को एआईआईबी द्वारा दिए जाने वाले ऋण को संभवतः सबसे रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इस अवसर पर वित्त मंत्री वाग्ले ने एआईआईबी की नई अध्यक्ष को बधाई दी और संस्थापक सदस्य के रूप में नेपाल को दिए जा रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने एआईआईबी के वित्तीय सहयोग से चल रही पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने तथा एक्सप्रेसवे से संबंधित अध्ययन को भी शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया।

यूक्रेन, ब्लैक सी की सुरक्षा को लेकर कूटनीतिक प्रयास तेज करेगा तुर्किए : सूत्र

अंकारा। तुर्किए ने कहा है कि वह यूक्रेन संघर्ष के समाधान और काला सागर (ब्लैक सी) में नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज करेगा। तुर्किए सरकार के एक सूत्र ने रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती को यह जानकारी दी। सूत्र के अनुसार, तुर्किए सरकार समुद्री यातायात की सुरक्षा बहाल करने, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संघर्ष को और फैलने से रोकने के लिए संबंधित पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखेगी। सूत्र ने कहा कि तुर्किए का मानना ​​है कि काला सागर को युद्ध क्षेत्र नहीं बनना चाहिए और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तथा समुद्री मार्गों पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्किए बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और ब्लैक सी में दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए परिस्थितियां तैयार करने के उद्देश्य से कूटनीतिक प्रयास तेज करेगा। सूत्र ने बताया कि तुर्किए नौवहन की सुरक्षा को संघर्ष की ओर बढ़ने से रोकने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में से एक मानता है। इसके लिए तुर्किए रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संपर्क बनाए रखने और ऐसा तंत्र विकसित करने की कोशिश करेगा, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें। उन्होंने कहा कि तुर्किए कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू कराने और यूक्रेन की सीमाओं से बाहर संघर्ष फैलने के जोखिम को कम करने के लिए करता रहेगा। तुर्किए के राष्ट्रपति रैसेप तैयप एर्दोग़न पहले भी काला सागर की सुरक्षा को लेकर बातचीत की जानकारी दे चुके हैं। वहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पैसेकोव ने पुष्टि की है कि तुर्किए ने काला सागर की सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव रूस के सामने रखे हैं। हाल के महीनों में काला सागर में समुद्री नागरिक बुनियादी ढांचे और व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, जुलाई में यूक्रेनी ड्रोन हमले में काला सागर में तुर्किए के ड्राई कार्गो जहाज एमवी रेहान सारी को नुकसान पहुंचा था, जिसमें एक नाविक की मौत और तीन अन्य के घायल होने की बात कही गई। इसके अलावा, नोवोरोस्सियस्क बंदरगाह के पास तुर्किए के ड्रॉडे गॉइले ड्राई कार्गो जहाज एमवी गुलुक पर भी ड्रोन हमले की जानकारी सामने आई थी।

गुलवीर सिंह ने त्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ 1500 मीटर दौड़ में जीता रजत

आइची-नागोया। भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने एशियन खेल-2026 में पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर ने फाइनल में 3:36.72 मिनट का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। जापान के काजुटो इइज़ावा ने 3:36.35 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस दौरान नया एशियन खेल रिकॉर्ड भी बनाया। इइज़ावा ने गुलवीर को महज 0.37 सेकंड के अंतर से पीछे छोड़ा। जापान के ही नागिया मोरी ने 3:37.92 मिनट के समय के साथ कांस्य पदक जीता। गुलवीर शुरुआत से ही पदक की दौड़ में बने रहे। उन्होंने अंतिम चरण में अपनी गति बढ़ाते हुए मजबूत चुनौती पेश की, लेकिन इइज़ावा ने आखिरी कुछ मीटर में अपनी बढ़त बनाए रखी और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। भारत के यूनूस शाह 3:43.88 मिनट के समय के साथ नौवें स्थान पर रहे। यह गुलवीर का इन एशियन खेल में



दूसरा पदक है। इससे पहले वह पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भी रजत पदक जीत चुके हैं। हांगझोऊ एशियन खेल में उन्होंने 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था। अलीगढ़ के रहने वाले गुलवीर सिंह भारतीय सेना में नायब सुबेदार हैं। उन्होंने 2018 में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल होने के बाद एथलेटिक्स में लगातार

अपनी पहचान बनाई। वह 5000 मीटर, 10,000 मीटर, एक मील और हाफ मैराथन में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। 2025 में गुलवीर 4 मिनट से कम समय में एक मील दौड़ने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने 3:55.63 का समय निकाला था। इसी साल उन्होंने 59:42 के समय के साथ एक घंटे से कम समय में

हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव भी हासिल किया। इनडोर 5000 मीटर में 12:59.77 का समय निकालकर वह 13 मिनट से कम समय में दौड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट भी बने थे। गुलवीर फरवरी 2025 से टारगेट ओलंपिक पोटियम स्कोम (टॉप्स) के तहत सहायता प्राप्त एथलीट हैं। एशियन खेल की तैयारी के लिए उन्हें अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी और जरूरी खेल उपकरणों के लिए सहायता मिली है। एशियन खेल चक्र के दौरान टॉप्स के तहत उन्हें 23,29,270 रुपये और वार्षिक प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता कैलेंडर के तहत 17,10,825 रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। इस रजत पदक के साथ एशियन खेल 2026 में भारत के पदकों की संख्या 41 हो गई है। भारत के खাতে में अब चार स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में भारत 12वें स्थान पर है।

मुंबई इंडियंस ने 10 खिलाड़ियों को किया रिटेन, छह को किया रिलीज



नई दिल्ली। महिला प्रीमियर लीग-2027 (डब्ल्यूपीएल) की मिनी नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है। टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत 10 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है, जबकि छह खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। मुंबई इंडियंस के लिए पिछला सत्र निराशाजनक रहा था। टीम पहली बार डब्ल्यूपीएल के इतिहास में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। शुरुआती तीन सत्रों में सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीमों में शामिल रही मुंबई को पिछले सत्र में लगातार अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और वह केवल एक बार लगातार दो मुकाबले जीत सकी। नए कोच ल्यूक विलियम्स के मार्गदर्शन में हरमनप्रीत कौर को अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस अब अपने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ

घरेलू क्रिकेट के कुछ और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जोड़कर टीम को मजबूत करना चाहेगी। डब्ल्यूपीएल-2027 के लिए मुंबई इंडियंस की रिटेन खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नैट स्किवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, शबनम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फ़िरदौस और निकोला कैरी। रिलीज खिलाड़ी जी. कमालिनी, मिली इलिंगवर्थ, नन्हा क्रांति रेड्डी, पूनम खेमनार, साइका इशाक और त्रिवेणी वशिष्ठ। डब्ल्यूपीएल-2027 की मिनी नीलामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में आयोजित की जाएगी। नीलामी में मुंबई इंडियंस अपनी टीम में खाली स्थानों को भरने के साथ घरेलू प्रतिभाओं को जोड़ने पर ध्यान देगी।

विथ्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में जीता कांस्य, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

आइची-नागोया। भारतीय एथलीट विथ्या रामराज ने एशियन खेल-2026 में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। विथ्या ने फाइनल में 54.75 सेकंड का समय निकालकर यह उपलब्धि हासिल की। विथ्या ने अपना ही साझा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। इससे पहले 55.42 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड विथ्या रामराज और महान धाविका पीटी उपा के नाम संयुक्त रूप से था। विथ्या ने 2023 हांगझोऊ एशियन खेल में इस समय की बराबरी की थी। अब नागोया में 54.75 सेकंड का समय निकालकर उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विथ्या ने प्रतियोगिता के होट चरण में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 55.73 सेकंड के सीजन के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात की मरियम करीम ने 54.31 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कजाकिस्तान की एडेलिना जेम्स 54.58 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। भारत की अनु राघवन

55.88 सेकंड के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। विथ्या का एशियन खेल में यह लगातार दूसरा पदक है। उन्होंने 2023 हांगझोऊ एशियन खेल में भी 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता था। इससे पहले वह 2022 एशियन खेल की मिश्रित 4म400 मीटर रिले टीम में रजत पदक जीत चुकी हैं। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया था। तमिलनाडु के कोयंबटूर की रहने वाली विथ्या 400 मीटर बाधा दौड़ के साथ 4म400 मीटर रिले में भी भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत की 4म400 मीटर रिले टीम का भी हिस्सा रही थीं। विथ्या दिसंबर 2023 से टारगेट ओलंपिक पोटियम स्कोम (टॉप्स) के तहत सहायता प्राप्त एथलीट हैं। एशियन खेल की तैयारी के लिए उन्हें राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में प्रशिक्षण और विभिन्न उपकरणों की खरीद के लिए टॉप्स के तहत वित्तीय सहायता मिली है।



लेवर कप जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ जश्न मनाती टीम यूरोप। टीम में कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, कैस्पर रूड, याकूब मैसिक और अन्य खिलाड़ी शामिल रहे।

व्यापार समाचार

संक्षिप्त समाचार

आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट, रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कंपनियों को राहत देते हुए कर ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने सोमवार को 'एक्स' पोस्ट पर जारी बयान में बताया कि कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 21 नवंबर कर दिया गया है। साथ ही कर ऑडिट की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के %एक्सप्लेनेशन 2 के तहत दी गई टेबल में क्रम संख्या 2 पर बताए गए लोगों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का इनकम रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख अब अक्टूबर, से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी गई है। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की %तय तारीख% को भी 21 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि इस खबर में सबसे जरूरी बात दो तारीखों और दो कामों का फर्क है। 21 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी है, जबकि 21 नवंबर तक आईटीआर भरना है। ये दोनों काम एक नहीं हैं।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में भी बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली। 'ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे थे। हालांकि डाउ जॉन्स स्पूचर्स सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। वहीं एशियाई बाजार में आज आमतौर पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के इरानी प्रस्ताव को खारिज कर दिए जाने के कारण दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजारों में आज दबाव का रुख बन गया है। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती दिखाते में सफल रहे थे। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 7,743.41 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। इसी तरह नैस्डैक ने 129.34 अंक यानी 0.48 प्रतिशत की मजबूती के साथ 27,068.72 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया था। हालांकि, डाउ जॉन्स स्पूचर्स आज फिनाहल 180.38 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 51,648.24 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले क्षेत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए थे। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से एफटीएसई इंडेक्स में कोई हलचल नहीं हुई थी। वहीं सीएसपी इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 8,077.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। इसके विपरीत डीएएसक्स इंडेक्स ने 142.11 अंक यानी 0.56 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,408.64 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं, एशियाई बाजार में आज आमतौर पर दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ बाजार में से छह के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि दो सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से ताइवान वेटेड इंडेक्स में आज कोई हलचल नहीं हो रही है। एशियाई बाजार में हेंग सेंग इंडेक्स 148.91 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,659 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.64 प्रतिशत उछल कर 5,747.40 अंक के स्तर पर आ गया है। दूसरी ओर, गिफ्ट निफटी 0.22 प्रतिशत लुढ़क कर 23,138.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

नई दिल्ली। कोटनाशक और फफूंदनाशक जैसे एग्रोकेमिकल्स का उत्पादन और कारोबार करने वाली कंपनी शिवकेम एग्रो लिमिटेड का 14.01 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 30 सितंबर तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद एक अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि पांच सितंबर को अलॉटिड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर छह अक्टूबर को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद दोपहर 2:15 बजे तक यह आईपीओ सिर्फ 9 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 59 रुपये से लेकर 62 रुपये प्रति शेयर का

माउंट एवरेस्ट क्लअरीज ने आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष दाखिल किया डीआरएचपी

नई दिल्ली। इंदौर की कंपनी माउंट एवरेस्ट क्लअरीज लिमिटेड ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) के माध्यम से फंड जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास ड्राफ्ट रेंड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास जमा मसौदा दस्तावेज के अनुसार माउंट एवरेस्ट क्लअरीज लिमिटेड के 10 रुपये फेस वैल्यू वाला यह आईपीओ एक बुक बिल्ड इश्यू है, जिसमें पूरी तरह से 1.15 करोड़ इश्ट्री शेयरों का एक नया इश्यू शामिल है। इनके शेयरों को एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। कंपनी इस ताजा इश्यू से मिलने वाली राशि में से 230 करोड़ रुपये का उपयोग 10 लाख हेक्टेोलीटर प्रति वर्ष (एचएलपीए) की क्षमता वाली एक नई ब्लूइंग (बीयर निर्माण) सुविधा स्थापित करने के लिए



प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 2,000 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 4,000 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके

लिए उन्हें 2,48,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 5 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 22.60 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इस आईपीओ में

सर्राफा बाजार में मामूली गिरावट, सोना और चांदी की चमक पड़ी फीकी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान सकेतिक गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में अब बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,52,670 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,52,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,39,940 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,40,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी मामूली कमजोरी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 244,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

एशियन खेल 2026 : भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर पुरुष स्कैथ के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

आइची-नागोया। गत चैंपियन भारत ने एशियन खेल 2026 में सोमवार को पुरुष स्कैथ टीम स्पर्धा के ग्रुप चरण में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ भारत ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत के लिए वेलावन सैथिलकुमार ने जीत की शुरुआत की। उन्होंने दक्षिण कोरिया के ना जूयंग को सीधे तीन गेम में 11-6, 11-4, 11-7 से हराया। वेलावन ने पहले गेम से ही मुकाबले पर नियंत्रण बनाए रखा और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद अभय सिंह ने यू जियॉंगमिन को 11-4, 11-7, 11-1 से हराकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। अभय ने पहले गेम में आसानी से जीत दर्ज की और इसके बाद लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। मुकाबला भारत के पक्ष में तय होने के बाद वीर चोत्रानी ने दक्षिण कोरिया के ओह सोजिन को 11-6, 11-4, 11-2 से हराकर भारत को 3-0 की शानदार जीत दिला दी। भारत ने इससे पहले ग्रुप चरण के अपने शुरुआती मुकाबले में चीन को भी 3-0 से मात दी थी। लगातार दो जीत के साथ भारतीय टीम ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के बाद एशियन खेल 2026 में भारत के पदकों की संख्या 40 हो गई है। भारत के खते में अब चार स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य पदक हैं और वह पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।

एशियन खेल : मुक़ेबाज कपिल पोखरिया सेमीफाइनल में, भारत का एक और पदक पक्का

आइची-नागोया। भारतीय मुक़ेबाज कपिल पोखरिया ने एशियन खेल-2026 में सोमवार को पुरुषों के 90 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ कपिल ने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया। कद का फायदा मिलने के कारण कपिल ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामकता रख अपनाया। पहले राउंड में उनके बाएं हाथ के हुक लगातार निशाने पर लगे और उन्होंने पांचों जजों का समर्थन हासिल करते हुए 5-0 से राउंड अपने नाम किया। दूसरे राउंड में भी कपिल ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। उन्होंने कई सटीक मुक़े लगाए और किम पर लगातार दबाव बनाए रखा। भारतीय मुक़ेबाज के लगातार प्रहारों के बाद दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी को रैटिंग काउंट भी दिया गया, हालांकि वह मुकाबला जारी रखने में सफल रहे। कपिल ने यह राउंड भी 5-0 से जीता, हालांकि एक जज ने किम को 8 अंक दिए। तीसरे राउंड में किम ने आक्रामकता बढ़ाई, लेकिन कपिल ने अपने मुक्कों की सटीकता और बेहतर नियंत्रण के दम पर बहुत बनाए रखी। उन्होंने मुकाबले के अंत तक अपना दबदबा कायम रखा। अंततः पांचों जजों ने कपिल के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें 5-0 से विजेता घोषित किया गया। इस जीत के साथ कपिल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और अब उनकी नजर स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाने पर होगी। इससे पहले भारतीय मुक़ेबाज लवलीना बोर्गोहेन और प्रिया भी अपने-अपने वर्गों के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। लवलीना ने महिलाओं के 75 किग्रा क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियॉंग सुयोन को, जबकि प्रिया ने महिलाओं के 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान की मिजगोना समादोवा को हराया था।

शिवकेम एग्रो का आईपीओ लॉन्च, 30 सितंबर तक लगा सकते हैं बोली



क्रालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 4.78 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 45.31 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 44.87 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.04 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए शर्जॉन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि मांशीतला सिक्वोरिटोज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। निंकुज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है। शिवकेम एग्रो की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए रेंड हेरिंग

प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 1.29 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 2.60 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 3.25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 10.95 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 27.50 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 33.84 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में उतार-चढ़ाव होता रहा।

एफएक्स मल्टिट्रेक की स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री, प्रीमियम लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

नई दिल्ली। एचबीएस और इंडस्ट्रियल रफ़िनेशन का काम करने वाली कंपनी एफएक्स मल्टिट्रेक के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में प्रीमियम एंट्री कर अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 116 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 6.08 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 123.05 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण ये शेयर कुछ देर में ही फिसल कर 117 रुपये के स्तर तक गिर गए। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही

खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी, जिससे इस शेयर की चाल में तेजी आ गई। खरीदारी के सपोर्ट से कंपनी के शेयर 129.20 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर आ गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 13.20 रुपये यानी 11.38 प्रतिशत का फायदा हो गया। इस कंपनी का 45 करोड़ रुपये का आईपीओ 21 से 23 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिसर्प्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरअब्स 17.72 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला एवमे यूनिवर्सल का पब्लिक इश्यू, 6 अक्टूबर को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खासकर इंडस्ट्रियल सेफ्टी फूटवियर बनाने वाली कंपनी एक्मे यूनिवर्सल सेफजोन 9 लिमिटेड का 35.93 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 30 सितंबर तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद एक अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि पांच सितंबर को अलॉटिड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर छह अक्टूबर को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद दोपहर 2:40 बजे तक यह आईपीओ सिर्फ 9 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 65 रुपये से लेकर 71 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,600 शेयर का है। इस आईपीओ

में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 3,200 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,27,200 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 50,60,800 नए शेयर जारी हो रहे हैं। इस आईपीओ में क्रालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 59.03 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 25.90 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 11.15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 3.92 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए एक्सपर्ट ग्लोबल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि मां शीतला सिक्वोरिटोज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वकील राकेश रावल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

जबलपुर हाईकोर्ट ने 7 घंटे के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए निर्देश

भोपाल। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में विगत दिनों वकील राकेश रावल से थाने में हुई मारपीट का मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज सोमवार को जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने भोपाल के वकील राकेश रावल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस को वकील को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने घटना की सच्चाई जानने के लिए 7 घंटे का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। वकील राकेश रावल के अनुसार, खटलापुरा मंदिर के पास पुलिस बैरिकेडिंग हटाने को लेकर विवाद हुआ। उनका आरोप है कि पुलिसकर्मी उन्हें थाने ले गए और मारपीट की। पुलिस का दावा है कि वकील ने सरकारी काम में रुकावट डाली थी। बता दें कि 22 सितंबर को शाम करीब 8 बजे हुए



घटनाक्रम के बाद राकेश रावल की शिकायत पर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर सख्दकदर्ज की गई थी। जबकि आरक्षक हरि ओम वर्मा की शिकायत पर राकेश रावल के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा,अभद्रता और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। विवाद के बाद डीसीपी जोन-1 ने थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। घटना

के बाद वकीलों में नाराजगी फैली और उन्होंने जहांगीराबाद थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। लोगों की नाराजगी देख थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार समेत तीन पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित किया गया। दोनों पक्षों की क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई। अब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से मामले की दिशा तय होगी। फिलहाल,अदालत के इस रुख से पीड़ित वकील को राहत मिली है,जबकि

आगामी सुनवाई में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। अगली सुनवाई 16 नवंबर तक होने की उम्मीद है। अधिवक्ता राकेश रावल (45) ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 8 बजे वे खटलापुरा मंदिर की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उनका वाहन रोक लिया और उन्हें थाने चलने के लिए कहा। रावल ने वाहन में पेट्रोल नहीं होने की बात कही तो पुलिसकर्मी गाली-गलौज करने लगे। रावल के मुताबिक, विरोध करने पर उन्हें कीचड़ में पटककर डंडे बरसाए गए। रावल के मुताबिक,कंट्रोल रूम तिराहे पर रास्ता बंद होने के कारण पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका था। उन्होंने बेरागढ़ जाने का वैकल्पिक रास्ता पूछा। पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे रास्ता बताने के लिए खड़े नहीं हैं। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। दूसरी ओर, थाना प्रभारी (निलंबन से पहले) राजन सिंह अहिरवार का कहना था कि विवाद के दौरान अधिवक्ता ने ट्रैफिक एसपी अजय बाजपेई के साथ बदसलूकी की थी।

सड़कों की मरम्मत और रेस्टोreshन के कार्य में तेजी लाई जाए : संस्कृति जैन

राजधानी भोपाल की खराब सड़कों को लेकर नगर निगम आयुक्त ने दिये निर्देश

भोपाल। बारिश के दौरान शहर की सड़कों पर हुए गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत अब तेज गति से कराने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सोमवार को निगम मुख्यालय अटल भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्य मार्गों सहित अन्य सड़कों के गड्ढे भरने और आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कराने को कहा। निगम आयुक्त ने कहा कि वर्षाकाल समाप्त होने के बाद सड़कों की मरम्मत के कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही मरम्मत और रेस्टोreshन के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर आगामी शुक्रवार तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सड़कों के गड्ढे भरने, मरम्मत, विभिन्न विकास योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। निगम आयुक्त ने साथे कार्यो की समीक्षा की गई। निगम आयुक्त ने सीमेंट कंक्रीट से बनी मुख्य सड़कों की मरम्मत के सप्ते 9 मीटर और 7.5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों की मरम्मत के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। रेस्टोreshन कार्य की गुणवत्ता पर



नजरनिगम आयुक्त ने जलप्रदाय और सीवेज संबंधी कार्यों के बाद सड़कों पर किए गए रेस्टोreshन कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अमृत योजना के तहत किए गए कार्यों के बाद रेस्टोreshन कार्यों का निरीक्षण यांत्रिकी विभाग के इंजीनियरों से कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रस्तावित रेस्टोreshन कार्यों की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सीवेज और पेयजल पाइप लाइन विछाने के बाद सड़कों का रेस्टोreshन निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जाए। सीवेज लाइनों के मेनहोल को आवश्यकता के अनुसार शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए। अमृत योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों को जल्द शुरू करने के साथ कार्यस्थलों पर नागरिकों की आवाजही सुनाम बनाए रखने के लिए गड्ढों को अस्थायी रूप से भरकर समतलीकरण काने को कहा गया।

न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर अस्थायी श्रमिकों का भोपाल में धरना

भोपाल। राजधानी भोपाल में न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर अस्थायी,अंशकालीन, चौकीदार और ठेका श्रमिकों ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना दिया। 3 से 8 हजार रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के सामने नारेबाजी करते हुए ‘न्यूनतम वेतन दिलाओ उपवास आंदोलन’ शुरू किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल को वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती की ओर से की गई घोषणा की याद दिलाई। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में घोषित न्यूनतम मजदूरी और उन्हें मिल रहे वास्तविक भुगतान के बीच बड़ा अंतर है। अस्थायी,आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 12,425 से 16,769 रुपए प्रति माह घोषित की है। उनका दावा है कि इसके बावजूद सरकारी विभागों में कई कर्मचारियों से 3 से 5 हजार रुपए में काम कराया जा रहा है। शर्मा के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्रों में भी ठेका श्रमिकों को पूरी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। इससे अस्थायी और ठेका कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि आंदोलन की पूर्व सूचना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल को पत्र के माध्यम से दी गई थी।

भोपाल में तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार की टक्कर से छात्रा की दर्दनाक मौत

भोपाल। राजधानी भोपाल के होली फैमिली स्कूल के सामने तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार की टक्कर से 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा सायमा शाहिद की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब सायमा अपनी सहेलियों के साथ सड़क पर टहल रही थी। गंभीर रूप से घायल सायमा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना 26 सितंबर शनिवार की है। सोमवार को परिरज भोपाल पहुंचे, इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार सायमा मूल रूप से वैशाली, बिहार की रहने वाली थी और भोपाल के मौलाना आजाद कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह पढ़ाई के लिए भोपाल में रह रही थी। हादसे की सूचना कॉलेज प्रबंधन की ओर से परिरजों को दी गई। सायमा के चाचा मोहम्मद आरिफ ने बताया कि कॉलेज के नौशाद सर ने फोन कर उन्हें हादसे की जानकारी दी थी। सूचना मिलने के बाद वे भोपाल पहुंचे। आरिफ का आरोप है कि कॉलेज में छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से सायमा को गांधी नगर स्थित हाईटेक सिटी में कमरा लेकर रहने के लिए कहा था। सायमा करीब दो महीने से इसी कमरे में रह रही थी। हॉस्टल होता तो आसानी से सायमा बाहर नहीं आती और शायद हादसा टल जाता।

उप निर्वाचन क्षेत्रों और नगर परिषद सुसनेर में मतदान दिवस पर अवकाश

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 पूर्वाध के घोषित कार्यक्रम अनुसार मतदान दिवस 29 सितम्बर, 2026 को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। जिला आगर-मालवा की नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद का निर्वाचन होगा। जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि पंचायतों में मतदान 29 सितम्बर की सुबह 7 से अपनान्ह 3.00 बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी। सरपंच,जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतगणना 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगी। इसी दिन सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। जिला पंचायत सदस्यों एवं पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 अक्टूबर 2026 को प्रातः10.30 बजे से की जायेगी। उन्होंने बताया कि पंचायत उप निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य के 7, जनपद पंचायत सदस्य के 28, सरपंच के 110 और 4090 पंच पद के लिये उप निर्वाचन होगा।

राज्य सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है : मुख्यमंत्री मोहन यादव



मुख्यमंत्री ने बलराम कृषि महोत्सव में अनुपपुर के किसानों से किया वरुअल संवाद

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनुपपुर का बड़ा योगदान है। अनुपपुर जिला जल संपदा से संपन्न है। जिले में केवई उद्देहन सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से ‘कृषक कल्याण वर्ष-2026’ के अंतर्गत अनुपपुर में आयोजित ‘बलराम कृषि महोत्सव’ में वरुअली जुड़कर किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तकनीक और नवाचार से कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता का विस्तार करना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश में किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध

कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी सेवा-संकल्प अभियान के अंतर्गत किसान हितैषी योजनाओं की जानकारीयां अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा की जाए। राज्य सरकार युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्वार, बाजरा जैसे श्रीअन्न के साथ धान उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। उन्होंने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान चौपालें लगाकर किसान हितैषी योजनाओं का प्रसार-प्रचार किया जाए। किसान चौपालों के माध्यम से किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अनुपपुर में धान, गेहूँ, दलहन और तिलहन के उत्पादन के साथ हमारे किसान नई तकनीक और नई फसलों को अपना रहे हैं। किसानों द्वारा

मशरूम और स्ट्रॉबेरी की खेती का जा रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियां अपनाते हुए नवीन तकनीक और नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कृषि का भविष्य उज्ज्वल है, किसान अपने बच्चों को कृषि उद्योगों से जोड़े। राज्य सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आरंभ हुई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना का लाभ दूरदराज के गांव वालों को मिलेगा। ग्रामीणों के लिए निःशुल्क रजिस्ट्री की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई है। राज्य सरकार बच्चों की बेहतर पढ़ाई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही हैं। बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने अनुपपुर जिले के प्रगतिशील किसानों से वरुअल संवाद किया। किसानों ने कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों, कृषि यंत्रीकरण, जैविक चन्द्रबंशी ने आधुनिक कृषि यंत्रों एवं सिंचाई सुविधाओं से प्राप्त लाभ बताए। प्रेमलाल केवट ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जबकि रामभजन ने फसल प्रदर्शन एवं किसान खेत पाठशाला की जानकारी दी। पशुपालक माधव सिंह राठौर ने उन्नत पशुपालन एवं कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से बड़े दुग्ध उत्पादन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने किसानों को प्रोत्साहित किया।

मंत्री नागर सिंह और इंदरसिंह ने सुनीं कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं



भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को केबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और इंदरसिंह परमार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं और सुझाव सुने। मंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मंत्रियों के समक्ष विभिन्न विभागों से भेजे प्रकरण रखे गए। जिन मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई आवश्यक थी, उन्हें संबंधित विभागों को भुंजकर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। मंत्री नागर सिंह चौहान और इंदरसिंह परमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का गंभीरता से परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण और उन्हें शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ दिलाता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

एसआईआर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर पुलिस से झड़प

भोपाल निर्वाचन कार्यालय का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया

भोपाल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, अरेरा हिल्स तक पैदल मार्च के बाद कार्यकर्ताओं ने घेराव का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता ब्रिकेड्स पर चढ़ गए और पुलिस से धक्का-मुक्की हुई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की। कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया,नए मतदाताओं के पंजीयन और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। हरीश चौधरी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होना

जरूरी है। जीतू पटवारी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बना रहना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उमंग सिंधार ने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब तथ्यों और पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। एक कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुछोटा पहनकर जंजीरों में बंधा हुआ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करता नजर आया। पटवारी और सिंधार भी उसके साथ दिखाई दिए। कुछ कार्यकर्ताओं के बैरिकेड्स पर चढ़ने के वीडियो भी सामने आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने मौडिया में छपी 25 सितंबर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें नए मतदाताओं के पंजीयन, मतदाता नाम हटाने-बहाल करने, फॉर्म- 6 और मतदाता सूची के डिजिटल डेटा से जुड़े मुद्दे शामिल थे। वहीं,निर्वाचन आयोग ने इन आपत्तियों को सामान्य विचार-विमर्श का हिस्सा बताते हुए अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने दोनों आयुक्तों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के बीच कई नए निर्णय भी लिए हैं।

तकनीक उपयोग और जनसेवा प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला है : कैलाश मकवाणा

उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने की पुलिस महानिदेशक से भेंट

भोपाल। पुलिस मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से भेंट कर पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर डीजीपी श्री मकवाणा ने मध्यप्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिसिंग में तकनीक के बढ़ते उपयोग, सामुदायिक पुलिसिंग, साइबर अपराध नियंत्रण, नक्सल समस्या के समाधान तथा कानून-व्यवस्था एवं प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर



प्रशिक्षुओं से संवाद किया।डीजीपी श्री मकवाणा ने मध्यप्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री के.एफ. रस्तमजी के योगदान को स्मरण करते हुए उनके

कार्यकाल के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर चर्चा की। उन्होंने चंबल क्षेत्र में डकैती की समस्या तथा उसे समाप्त करने के लिए किए गए पुलिस प्रयासों की जानकारी भी

प्रशिक्षुओं से साझा की। डीजीपी श्री मकवाणा ने बताया कि मध्यप्रदेश ने नक्सल समस्या के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने प्रदेश को नक्सलमुक्त बनाने के लिए अपनाई गई पुलिसिंग और रणनीति के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी दी। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिसिंग तथा संवेदनशील परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया।उन्होंने सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके लिए प्रशिक्षण एवं अधीसंरचना से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के

प्रभावो क्रियान्वयन, ई-समन जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं और पुलिसिंग को आधुनिक एवं अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि नशा मुक्त भारत-2029 के लक्ष्य की दिशा में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत विभिन्न अभियान से चालित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच विश्वास एवं संवाद को और मजबूत करना है। डीजीपी

श्री मकवाणा ने पुलिसिंग में तकनीक के बढ़ते उपयोग की जानकारी देते हुए बताया कि डायल-112 एवं एफआरवी व्यवस्था, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस सहित विभिन्न तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस के माध्यम से पुलिस कार्यालयों को पेपरलेस बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं ईएचआरएमएस में लगभग एक लाख पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा चुका है।उन्होंने पुलिस बल की कार्यक्षमता और कल्याण से जुड़े प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि तनाव प्रबंधन के लिए पिछले वर्ष हार्टफुलनेस

संस्था के साथ एमओयू किया गया है और इसके माध्यम से पुलिसकर्मियों के स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कार्य किया जा रहा है। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी का व्यवहार अच्छा और संवेदनशील होना चाहिए। जनता को जब पुलिस से मदद की आवश्यकता हो, तब उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. विनीत कपूर, पीएसओ टू डीजीपी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को डीजीपी कैलाश मकवाणा के कार्यों एवं पुलिस सेवा के अनुभवों से परिचित कराया।